



समीक्षा इंस्टीट्यूट

A Center of Excellence for Knowledge, Skills & Aptitude

Daily Answer Writing test

Marks

57 (2019)
49 (2020)

Test ID :

05

Date :

15 Oct. 2020

Time

90

mint.

SUBJECT

Paper-3 (part-B) 7.10 to 7.17

Model Answer key

Student Name

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Candidate's Mobile No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Student Name

--

Invigilator Signature

--

JOIN US

☎ 98262-28312, 90745-85746, 77708-38222

Follow us on : [Telegram](#) [WhatsApp](#) [Facebook](#) [Globe](#) [Instagram](#) | [Subscribe YouTube Channel](#) [YouTube](#)



समीक्षा इंस्टीट्यूट

Direction -

Q. NO. 1 प्रश्न क्रमांक 01 में कुल 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर एक या दो पंक्ति में देना है। सभी प्रश्न ए से ओ तक हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का है।

3*15= 45

(A) अल्पकालीन साख ।

उत्तर-

1. अवधि- सामान्यतः 15 माह होती है।
2. उद्देश्य- बीज, उर्वरक, चारा, मजदूरी भुगतान हेतु।
3. संस्थाएँ- नाबार्ड, सहकारी संस्थाएँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक आदि।

(B) सहकारी ऋण समिति की स्थापना किसने व किसकी सिफारिश पर की।

उत्तर- सहकारी ऋण समिति की स्थापना फेड्रिक निकलसन द्वारा एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी।

(C) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ।

उत्तर-

1. वर्ष 1965 में स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान।
2. उत्पादकों के स्वामित्व और उनके द्वारा संगठित नियंत्रित संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु।
3. वर्तमान में इसके चेयरमेन श्री दिलीप राठ है व इसका मुख्यालय आनन्द शहर (गुजरात) में है।

(D) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

उत्तर- 1960 के दशक में प्रारंभ यह एक प्राथमिक समाज कल्याण एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सरकार कम मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराती है। जैसे- दाल, चावल, मोटे अनाज आदि।

(E) सब्सिडी क्या है व इसके कितने प्रकार है?

उत्तर- सब्सिडी का अर्थ किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन देना है। सब्सिडी दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सब्सिडी में नगद अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण व कर छूट, बीमा रेंट अप्रत्यक्ष सब्सिडी में आते है।

(F) मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ।

उत्तर-

1. वर्ष 1956 में स्थापित सहकारी विपणन समितियों की राज्यस्तरीय शीर्ष संस्था।
2. सहकारी विपणन को बढ़ावा तथा श्रेष्ठ कृषि उत्पादों का वितरण किसानों तक पहुँचाने के उद्देश्य से।
3. मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधि. 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था।

(G) खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा।

उत्तर- खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार “ सभी व्यक्तियों को सही समय पर भोजन उपलब्ध कराना होना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।”

(H) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

उत्तर-

1. वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पारित।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

2. पोषण युक्त भोजन एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से।
3. इसमें रियायती दरों पर (3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रतिकिलो ग्राम गेहूँ व 1 रुपये प्रतिकिलो ग्राम मोटे अनाज) भोजन उपलब्ध होता है।

(I) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ।

उत्तर-

1. वर्ष 1969 में स्थापित।
2. सहकारी आवास हेतु शीर्ष संगठन।
3. यह सहकारी समितियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकास करने और उनके समन्वय में संलग्न है।

(J) अंत्योदय अन्न योजना।

उत्तर-

1. अति निर्धन परिवारों तक वितरण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दिसम्बर 2000 में प्रारंभ।
2. इसमें 2 रुपये प्रतिकिलो ग्राम गेहूँ व 3 रुपये प्रतिकिलो ग्राम चावल की दर से 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार वितरण होता है।

(K) लघु उद्योग सहकारिता।

उत्तर- लघु उद्योगों में सहकारिता को प्रोत्साहन करने हेतु इसके अंतर्गत श्री महिला ग्रह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, इण्डियन कॉफी हाउस, मृगनयनी आदि उद्योगों का संचालन किया जा रहा है।

(L) चकबंदी।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

उत्तर- चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचालित किया जाता है। चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है। जिसमें कृषक के लिये कृषि विधियाँ सरल हो जाती है।

(M) किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

उत्तर- 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के द्वारा सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 43(A) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है।

(N) भारत में सहकारी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ।

उत्तर- लोकतंत्र, समानता व सहायता के आधार पर संपूर्ण समुदाय के लिये कार्य करने हेतु सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किया गया।

(O) पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कृषि की महत्त्वता।

उत्तर- पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “ कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं।

Q. NO. 2. लघु उत्तरीय प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द (MPPSC 2019) है तथा किन्ही 10 प्रश्नों का उत्तर दें।

Write the Answer of any 10 of the following question in about 100 (MPPSC 2019)

6*10=60(MPPSC 2019)

(A) भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को स्पष्ट करें।

उत्तर- कृषि के महत्व को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है -



समीक्षा इंस्टीट्यूट

- सर्वाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- जी.डी.पी. की वृद्धि में सहायक।
- राष्ट्रीय आय में सहयोगी भूमिका।
- उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति करना।
- खाद्यान्न की आपूर्ति करना।
- राजस्व में योगदान।
- पूँजी निर्माण में सहयोगी भूमिका।
- पशुओं हेतु चारा।
- विदेशी व्यापार बढ़ाने में सहयोगी।
- विश्व में कृषि प्रधान देश (विशिष्ट पहचान) के रूप में जाना जाता है।
- पलायन की पृवृत्ति को अंकुश में रखना।
- पर्यावरण संतुलन बनाए रखना।
- बायोमास, बायोडीजल, बायोफर्टिलाइजर के उत्पादन में उपयोगी/सहयोगी।

(B) सामाजिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सब्सिडी।

उत्तर- सब्सिडी का अर्थ किसी आर्थिक, संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन देना है।

सेवाओं एवं वस्तुओं के उपभोग को समर्थन देने तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सामाजिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सब्सिडी- आयकर में छूट, जीवन बीमा, लोक वितरण प्रणाली, ऋण (PMRY) (Self help



समीक्षा इंस्टीट्यूट

Group), शिक्षा (पुस्तक, फीस) स्वास्थ्य (टीकाकरण, इलाज, दवा) पोषण (मात्रत्व व बाल) आदि के माध्यम से प्राप्त होती है।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से व्यक्ति विशेष को अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान कर मूलभूत सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

(C) ग्रामीण साख क्या है? इसके वर्गीकरण को समझाइए।

उत्तर- ग्रामीण साख एक प्रकार की प्रतिभूति (गारण्टी) है जिसके आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसका उपयोग सामान्यतः बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों हेतु किया जाता है।

यह साख व्यापारिक बैंकों, सहकारी संस्थाओं, साहूकारों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नाबार्ड आदि के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण साख को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

अल्पकालीन साख - इसकी अवधि सामान्यतः 15 माह होती है। यह बीज, उर्वरक, चारा, मजदूरी भुगतान आदि हेतु दी जाती है।

मध्यमकालीन साख - इसकी अवधि लगभग 5 वर्ष तक होती है यह कृषि उपकरण, सिंचाई व्यवस्था पशु आदि क्रय करने हेतु दी जाती है।

दीर्घ कालीन साख - इसकी अवधि 10-20 वर्ष तक होती है यह भारी उपकरण, भूखण्ड बढ़ाने, ऋण चुकाने हेतु दी जाती है।

(D) खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए।

उत्तर- खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे निम्न हैं-



समीक्षा इंस्टीट्यूट

- भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाना एक दुष्कर व श्रम साध्य कार्य है।
- उचित भण्डारण व्यवस्था के अभाव में भण्डारण का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालन की खामियाँ खाद्य सुरक्षा व बफर स्टॉक को महत्वहीन कर देती हैं।
- परिवहन व्यवस्था तथा आधारभूत संरचना में कमियों के चलते खाद्यान्न का भण्डारण व वितरण दोनों ही प्रभावित होते हैं।
- भारतीय कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है अतः सदैव उचित भण्डारण स्तर बनाए रखना आसान नहीं है।
- राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा प्रशासनिक शिथिलता के चलते यह योजना अपेक्षित लक्ष्यों से दूर है।

(E) ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे।

उत्तर- ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे निम्न है-

- जातिगत कठोरता - व्यवसायों का प्रतिबंध पाया जाता है।
- महिलाओं के शोषण की पृवृत्ति अभी भी बनी हुई है।
- छीजन समस्या (Drop outs) और प्रेरणा के अभाव में शिक्षा के आशानुरूप विकास नहीं हुआ है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के विलंब से आज भी लोग परंपरागत इलाज पर निर्भर हैं।
- वित्तीय संस्थाओं का लाभ अंदरूनी या दूरदराज के गाँवों तक नहीं पहुँच रहा है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

- धर्म एवं परंपरा अभी भी प्रभावशाली है।
- प्रशासनिक पहुँच आज भी गाँव के लिए दिवा स्वप्न है।
- नवीन तकनीकी पर सहज विश्वास की पृवृत्ति का अभाव
- हाइजेनिक प्रॉब्लम (साफ-सफाई)।
- आर्थिक संसाधनों की कमी।

(F) नगरीय क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे।

उत्तर- नगरीय क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- व्यक्तिवादिता की भावना- औपचारिक संबंध सहकारिता कम होना, मानसिक तनाव।
- भौतिक वादिता/दिखावा - अकर्मव्यता, निर्भरता।
- अलगाव और अवसाद - पारिवारिक व चारित्रिक विघटन।
- मलिन बस्तियाँ - नियोजन को प्रभावित करती हैं।
- जनसंख्या की अधिकता- मानवता का हास।
- आर्थिक विषमता में वृद्धि- संघर्ष, विरोध, अपराध।
- ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन।
- संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव।
- पर्यावरण असंतुलन की स्थिति व्याप्त।
- सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना की निम्न गुणवत्ता।
- आधारभूत संरचना का अभाव।
- नगरीकरण की बढ़ती समस्या।
- रोजगार सृजन की समस्या।
- अनियोजित शहरीकरण का होना।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

- गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि होना।
- अकुशल श्रमिकों का अधिक होना।

(G) भारत में बैंक एवं कृषि सहकारिता।

उत्तर- कृषि सहकारिता- इसके माध्यम से कृषि, बागवानी वन उत्पाद प्रसंस्करण, संचय, विपणन आदि की गतिविधियों को तीव्र करके कृषकों की जीवन स्तर में सुधार लाया गया। इस हेतु सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की। इसके निर्देशन में इफको, कृषकों, नाफेड, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन सहकारी संघ आदि सहकारी आंदोलनों का विकास हुआ है।

बैंक सहकारिता- इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय सहकारी बैंकों की संरचना को अपनाया गया है।

ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समिति

जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक

राज्य स्तर पर राजा सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक) स्थित है।

मध्यप्रदेश में इस भूमिका को नागरिक सहकारी बैंक, अम्बेडकर सहकारी बैंक, महिला सहकारी बैंक आदि के द्वारा निभाया जा रहा है।

(H) कृषि में सब्सिडी। इससे संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए।

उत्तर- कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जैसे -

प्रत्यक्ष सब्सिडी -



समीक्षा इंस्टीट्यूट

नलकूप, तालाब (बलराम ताल योजना), नुकसान की भरपाई (ओला वृष्टि), आदि के रूप में प्राप्त होती है।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी -

किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, पौध, कृषि उपकरण, बिजली पर छूट आदि के रूप में प्राप्त होती है।

मुद्दे -

- इसने फसल चक्र को नष्ट/ परिवर्तित कर के पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाया है। (उर्वरक की खपत बढ़ना आदि)
- यह सीमांत व छोटे कृषकों हेतु लाभकारी नहीं रही बल्कि धनी किसान ही लाभान्वित हुए हैं।
- इससे क्षेत्रीय विषमता में भी बढ़ोतरी हुई है।
- अधिकांश सब्सिडी लक्ष्य से परे रही है।
- अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल का स्तर घटा है।

(I) भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका।

उत्तर- यह विकास का प्रमुख सूचक है आज साक्षरता दर 74% है। प्रति एक किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय व प्रति 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, व्यवसायिक तथा उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का विस्तार विकास को प्रमाणित करते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं (PHC, CHC) का विस्तार, डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि, अस्पतालों व जीवन रक्षक दवाओं की सभी तक पहुँच, नियमित टीकाकरण आदि से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जो विकास की निशानी है। स्वस्थ युवा पीढ़ी



समीक्षा इंस्टीट्यूट

का निर्माण होने से कार्य दक्षता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है।

(J) ग्रामीण साख की बाधाएँ।

उत्तर-यद्यपि आज विभिन्न संस्थाएं ग्रामीण साख हेतु कार्य कर रही है किन्तु फिर भी निम्न बाधाएं इसमें दिखाई देती है।

- सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय संस्थाओं की पहुंच न होना।
- अत्यधिक औपचारिकता/ कागजी कार्यवाही।
- घूसखोरी।
- साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज वसूलना, हिसाब में गड़बड़ी रखना आदि।

कृषि साख बढ़ाने के उपाय- कृषि साख को आसानी से उपलब्ध कराने तथा वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं।

- व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार।
- सहकारी संस्थाओं का विस्तार।
- ऋण की मात्रा में वृद्धि।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में समन्वय।

(K) भारत में खाद्य सुरक्षा।

उत्तर- देश की समस्त जनसंख्या को खाद्य पदार्थ वर्ष भर सहजता से उपलब्ध रहे तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुलभता से प्राप्त हो सके। यही खाद्य सुरक्षा है खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार “सभी व्यक्तियों को सही समय पर आवश्यक भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।”



समीक्षा इंस्टीट्यूट

60 के दशक के शुरुआती दौर में भारत खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ जिससे भारत को खाद्यान्न आयात करना पड़ा। इससे सीख लेते हुए 1966-67 में हरित क्रांति का आगाज हुआ और देश को खाद्यान्न में आत्म निर्भरता होने लगी।

देश को पुनः ऐसी आपदा से बचाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में बफर स्टॉक योजना प्रारंभ की गई। जिसमें उपभोग के अतिरिक्त शेष खाद्यान्न का भण्डारण किया जाता है। जिससे खाद्य सुरक्षा व कीमतों पर नियंत्रण संभव हो पाता है।

(L) भारत में डेयरी सहकारिता।

उत्तर- दुग्ध उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसने दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता तथा सहकारिता से परिचित कराया जिससे देश में अमूल, साँची, पराग, विजया आदि सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुए तथा भारत विश्व में सर्वोच्च दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन सका। इससे दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर में भी सुधार सुनिश्चित हुआ है। परंतु अभी भी कुछ विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जैसे- तकनीकी सहायता को सभी दुग्ध उत्पादकों तक पहुँचाना, कृषि विशेषज्ञों से संवाद सुनिश्चित करना व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आदि।

Q.No.3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 300 शब्द (MPPSC 2019)

Answer the following question in about 300



समीक्षा इंस्टीट्यूट

words (MPPSC 2019) each

3*15 = 45 (MPPSC 2019)

A. भारत में सहकारिता आंदोलन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।

उत्तर- सहकारिता से तात्पर्य सहकार्य से है जिसमें निश्चित उद्देश्यों के अंतर्गत कुछ व्यक्ति मिल जुल कर कार्य करते हैं। अर्थात् सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का एच्छक संगठन है जो लोकतंत्र, समानता व सहायता के आधार पर सम्पूर्ण समुदाय के लिए कार्य करता है। इस आंदोलन का आधार सेवा है न कि लाभ।

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 से मानी जाती है। जबकि एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश के आधार पर फ्रेड्रिक निकलसन ने सहकारी ऋण समिति की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश में इसकी शुरुआत 1956 में म.प्र. राजा विपणन सहकारी संघ (MPMARKFED) की स्थापना से मानी जाती है।

सहकारिता आंदोलन को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

कृषि सहकारिता -

इसके माध्यम से कृषि, बागवानी वन उत्पाद प्रसंस्करण, संचय, विपणन आदि की गतिविधियों को तीव्र करके कृषकों की जीवन स्तर में सुधार लाया गया। इस हेतु सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की। इसके निर्देशन में इफको, कृषकों, नाफेड, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन सहकारी संघ आदि सहकारी आंदोलनों का विकास हुआ है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

डेयरी सहकारिता -

दुग्ध उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसने दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता तथा सहकारिता से परिचित कराया जिससे देश में अमूल, साँची, पराग, विजया आदि सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुए तथा भारत विश्व में सर्वोच्च दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन सका।

बैंक सहकारिता -

इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय सहकारी बैंकों की संरचना को अपनाया गया है।

ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समिति

जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक

चुनौतियाँ -

- सक्रिय भागीदारी में कमी (निष्क्रिय सदस्यता)
- NPA का बढ़ना
- सरकारी सहायता पर निर्भरता
- पेशेवर प्रबंधन की कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप

आज सहकारी आंदोलन, ग्रामीण साख, लघु उद्योग, कृषि विपणन, पशु देखभाल, ग्रामीण स्वच्छता आदि क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है। इसके महत्व को समझते हुए सरकार ने 2011 में 97वें वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके सहकारिता को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

B. नगरीय विकास एवं नगरीय क्षेत्र के मुद्दों का भारतीय संदर्भ में वर्णन कीजिए।

उत्तर- नगर से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसका घनत्व अधिक हो, जहाँ औपचारिकता और दिखाना पाया जाता है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है।

नगरीय विकास :-

नगरीय विकास को सामाजिक व आर्थिक संरचना के माध्यम से देखा जा सकता है।

आर्थिक संरचना :-

- यहाँ आधारभूत संरचना अर्थात् सड़क, बिजली, पानी आदि की उचित व्यवस्था होती है।
- संचार और परिवहन के विविध साधन मौजूद हैं।
- यहाँ पूर्ण विकसित वित्तीय संस्थाएं पायी जाती हैं (बैंक, बीमा, NBFC, आदि)।
- यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे पाये जाते हैं।
- यहाँ विनिमय का प्रमुख साधन मुद्रा है।
- उच्च तकनीकी के प्रयोग से कार्य शीघ्रता व सुविधा से सम्पन्न होते हैं।
- नगरों के नियोजित विकास हेतु नगर पालिका आदि जैसी संस्थाएं पायी जाती हैं।

सामाजिक संरचना :-

- नगरों में शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थाओं की उचित व्यवस्था एवं उच्च स्तर पाया जाता है स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

- यहाँ उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है जिससे स्वास्थ्य का स्तर भी उच्च रहता है प्रशिक्षित डॉक्टर, बड़े व सुविधा संपन्न अस्पताल आदि।
- यहाँ शिक्षा के कारण जाति व्यवस्था अपने कठोर रूप में दिखाई नहीं देती जैसे अंतर्जातीय विवाह, व्यवसाय का बंधन न होना आदि।
- यहाँ औपचारिक संबंधों की प्रधानता पायी जाती है जिसके चलते बंधन व नियंत्रण में शिथिलता पायी जाती है। को-लिविंग, नशे की पृवृत्ति अजनवीपन।
- यहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा के कारण लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है अधिकतम भौतिक उपभोग वाहन, भवन, मनोरंजन आदि।
- कुशल संचालन हेतु नगर कानून व्यवस्था से संचालित होते हैं। पुलिस, न्यायालय, जेल।

नगरीय क्षेत्र के मुद्दे :-

- व्यक्तिवादिता की भावना- औपचारिक संबंध, सहकारिता कम होना, मानसिक तनाव।
- भौतिक वादिता/दिखावा - अकर्मव्यता, निर्भरता।
- अलगाव और अवसाद - पारिवारिक व चारित्रिक विघटन।
- मलिन बस्तियाँ - नियोजन को प्रभावित करती हैं।
- जनसंख्या की अधिकता- मानवता का हास।
- नगरों की ओर पलायन।
- आर्थिक विषमता में वृद्धि- संघर्ष, विरोध, अपराध।

C. भारत के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के संदर्भ में सब्सिडी।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

उत्तर- सब्सिडी का अर्थ किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था व्यवसाय या व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन देना है।

आर्थिक क्षेत्र में सब्सिडी- सरकार द्वारा आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी में नगद अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि आते हैं। वहीं कर छूट, बीमा रेंट रिबेट, डेपरिसिएशन राइट ऑफ आदि को अप्रत्यक्ष सब्सिडी में शामिल किया जाता है।

मुद्दे-

- वित्तीय समावेशन के अभाव के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयुक्त व्यक्ति तक न पहुँचना।
- प्रशासनिक शिथिलता के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता में कमी।
- भ्रष्टाचार के कारण सब्सिडी का उचित लाभ न होना।

सामाजिक क्षेत्र में सब्सिडी -

सेवाओं एवं वस्तुओं के उपभोग को समर्थन देने तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान की जाती है। जैसे -

प्रत्यक्ष सब्सिडी -

छात्रवृत्ति, एल.पी.जी., बेरोजगारी भत्ता, कल्याणकारी योजनाएं (वृद्धावस्था पेंशन), लाइली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, सायकल प्रदाय, आदि के रूप में प्राप्त होती है।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी -



समीक्षा इंस्टीट्यूट

आयकर में छूट, जीवन बीमा, लोक वितरण प्रणाली, ऋण (PMRY) (Self help Group), शिक्षा (पुस्तक, फीस) स्वास्थ्य (टीकाकरण, इलाज, दवा) पोषण (मात्रत्व व बाल) आदि के माध्यम से प्राप्त होती है।

मुद्दे -

- अधिकांश सब्सिडी लक्ष्य से परे है।
- सब्सिडी प्राप्ति में जटिलताएं अधिक है।
- यह समय से प्राप्त न होने से महत्वहीन हो जाती है।
- सब्सिडी वाला खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण नहीं होता।
- सब्सिडी रहित क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान घटने लगता है।
- सब्सिडी द्वारा सरकार पर बोझ या राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है।
- एक बार प्रारंभ की गई सब्सिडी को हटाना लोकतंत्रीय सरकार के लिए मुश्किल फैसला है।
- बड़े देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कमजोर अर्थ व्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव डालती है।

D. लोक वितरण प्रणाली से क्या तात्पर्य है। इसकी कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए।

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक प्राथमिक समाज कल्याण तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सरकार कम मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है।

यह कार्यक्रम सरकार की नीति का प्रमुख अंग है। इसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, उपभोक्ता को उचित



समीक्षा इंस्टीट्यूट

दर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निर्धनता निवारण का प्रयास करना है।

मुद्दे -

- 1992 के बाद खाद्यान्न वितरण में गिरावट आयी फलतः खाद्यान्न के भण्डारण तथा सुरक्षा पर सरकार का व्यय बढ़ गया।
- उपयुक्त/ स्थायी पता न होने के कारण कई परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध न हो पाया जिसके चलते आधे से अधिक निर्धन इस वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित रह गए।
- यह व्यवस्था अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही।
- इसके बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की चोरी होती है।
- उचित मूल्य की दुकाने वितरण की जिम्मेदारी को उचित रूप से नहीं निभाती हैं।

1992 तक यह कार्यक्रम सभी उपभोक्ताओं के लिए सामान्य हकदार योजना थी। 1992 से दूरदराज, दुर्गम, पहाड़ी क्षेत्रों तक इसे पहुँचाने हेतु पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई।

1997 में इस प्रणाली में और सुधार अपनाते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। जिसमें गरीबी रेखा के आधार पर हितग्राही परिवारों का विभाजन किया गया।

अतिनिधन परिवारों तक वितरण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। जिसमें 2रु प्रति किलोग्राम गेहूँ व 3रु प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई। 2002 में इस



समीक्षा इंस्टीट्यूट

सीमा को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तक विस्तृत कर दिया गया।

इसी क्रम में वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया जिसमें 75% ग्रामीण जनसंख्या तथा 50% नगरीय जनसंख्या को कवर किया गया है जिन्हें 3रू/किग्रा. चावल, 2रू/किग्रा. गेहूँ तथा 1रू/किग्रा. मोटे अनाज की दर से 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है।

E. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के सूचकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर- विकास का अर्थ आगे बढ़ने से है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि का अनुभव किया जाता है तब उसे अर्थव्यवस्था का विकास कहा जाता है।

इसे निम्न सूचकों के माध्यम से समझा जा सकता है -

शिक्षा - यह विकास का प्रमुख सूचक है आज साक्षरता 74% है, प्रति एक किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय व प्रति 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, व्यवसायिक तथा उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का विस्तार विकास को प्रमाणित करते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सुविधाओं (PHC, CHC) का विस्तार डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि, अस्पतालों व जीवन रक्षक दवाओं की सब तक पहुँच, नियमित टीकाकरण आदि से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। जो विकास की निशानी है।



समीक्षा इंस्टीट्यूट

आधारभूत संरचना - रेल, सड़क, बंदरगाहों व हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि, बिजली-पानी की अबाध आपूर्ति विकास का संदेश देते हैं।

औद्योगिकीकरण - स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों ने आगे बढ़ते हुए नवरत्न और महारत्न जैसे दर्जे हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योगों की प्रतिष्ठा कायम की है। सेल, गेल, भेल आदि विकास के सूचक हैं।

नगरीकरण - नगरों में सभी सुविधाओं की उपलब्धता उन्हें विकास का पर्याय बनाती है पिछले दशकों में नगरों की संख्या (4,000 लगभग) तथा नगरीकरण (32%) में वृद्धि से विकास परिलक्षित होता है।

प्रति व्यक्ति आय - उद्योगीकरण और नगरीकरण ने देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया। साथ ही प्राथमिक व तृतीयक क्षेत्र के सहयोग से देश की प्रति व्यक्ति आय आज बढ़ कर 88,000/- प्रति वर्ष से अधिक हो चुकी है।

खाद्यान्न - आधुनिक तकनीकी तथा सिंचित रकबा बढ़ने से देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ कर 250 मिलि. टन से अधिक हो गया। जिससे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है।

विज्ञान - अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम (चंद्रयान, मंगलयान, PSLV, GSLV, क्रायोजेनिक इंजन आदि), मिसाइलों की क्षमता में वृद्धि (पृथ्वी, अग्नि, शृंखला, आकाश, नाग आदि) तथा दैनिक जीवन में उच्च तकनीकी का शामिल होना (मोबाइल, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव) विकास का प्रतीक है।

THE MARKS OF TRUST



समीक्षा इंस्टीट्यूट

Click here to join now



समीक्षाTM इंस्टीट्यूट
Sign of Success

MPPSC 2019
Mains Test Series
Second Batch
(Online/Offline)

Starting From

1 October, 2020



**REGISTER
NOW**

Contact : 98262-28312,
90745-85746, 77708-38222

